भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1519

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने हेतु उपाय

1519. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसादः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि की कम लाभप्रदता के कारण ग्रामीण युवाओं के कृषि कार्य से विमुख होने और बढ़ते पलायन का आकलन किया है,

(ख) क्या कृषि आय में कमी के कारण अगली पीढ़ी खेती करने से विमुख हो रही है, और

(ग) युवा किसानों के लिए कृषि को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का पलायन एक आम बात है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि से ग्रामीण युवाओं के पलायन का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः 59.5% (वर्ष 2023 में), 58.9% (वर्ष 2024 में) और 57.2% (वर्ष 2025 में) रहा है।

देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का आकलन समय-समय पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित "कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से किया जाता है। नवीनतम एनएसएस सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय 10,218 रुपये प्रति माह है। एसएएस के निष्कर्षों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय कृषि वर्ष 2012-13 में 6,426 रुपये से बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपये हो गई है।

कृषि राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ाने तथा कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सहायता करती है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने और किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए कई नीतियां, सुधार और विकास कार्यक्रम अपनाए और लागू किए गए हैं। ये विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हैं, जिनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिफल के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य कृषि को अधिक लाभकारी, सतत और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाना है, ताकि इसकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हो सके और कृषि क्षेत्र में युवाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुबंध** में संलग्न है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1519 "कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उपाय" विषय के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित अनुबंध।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
10. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
11 राष्ट्रीय बांस मिशन
12. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
14. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
15. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
16. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
17. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
19. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
20. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
21. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
22. नमो ड्रोन दीदी
23. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन
24. स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
25. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
26. डिजिटल कृषि मिशन
27. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
28. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

*****